



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1941 (श०)

(सं० पटना 664) पटना, वृहस्पतिवार, 6 जून 2019

सं० 16/सं.सं.-02-14/2006(खण्ड-I) सा0प्र0-7642
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 जून 2019

श्री अनिल कुमार झा, तत्कालीन अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना को धावादल द्वारा 10,000/- (दस हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने एवं दिनांक 18.10.2006 को अपराहन में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया गया जिसके कारण श्री झा को गिरफ्तारी की तिथि 18.10.2006 के अपराहन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) के प्रावधानों के तहत अधिसूचना झापांक 3319 दिनांक 22.11.2006 द्वारा निलंबित किया गया।

2. श्री झा द्वारा उक्त मामले में जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 12.12.2006 को योगदान देने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं०-3793 दिनांक 26.12.2006 द्वारा निलंबन से मुक्त मानते हुए योगदान स्वीकार किया गया।

3. इस मामले में श्री झा के विरुद्ध रिश्वत लिए जाने का आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (I) (i) (iii) के प्रतिकूल एवं भ्रष्टाचार का मामला होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ करने तथा निगरानी थाना कांड सं०-067/2006 के तहत अपराधिक मामला अन्वेषण एवं जाँच के अधीन होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री अनिल कुमार झा, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-3825 दिनांक

29.12.2006 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया एवं निलंबन की अवधि में मुख्यालय उद्योग (गन्ना विकास) विभाग निर्धारित किया गया।

4. उक्त मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के ससमय निष्पादन नहीं होने में आरोपित पदाधिकारी का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है अतएव विभागीय आदेश सं०-1827 दिनांक 14.05.2010 द्वारा श्री अनिल कुमार झा को पत्र निर्गमन की तिथि से निलंबन से मुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया।

5. श्री झा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से संबंधित उपर्युक्त आरोपों के लिए निगरानी थाना कांड सं०-067/2006 में प्रतिवेदित आरोपों के लिए मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 906 दिनांक 01.12.2006 द्वारा श्री अनिल कुमार झा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया गया। इस आलोक में विधि विभाग के आदेश सं०-4819 दिनांक 17.08.2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. श्री झा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के उपर्युक्त आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक-665 दिनांक 22.02.2007 तथा नये सिरे से संकल्प ज्ञापांक 6922 दिनांक 17.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2301/2009 में दिनांक 17.11.2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय पत्रांक 1828 दिनांक 14.05.2010 द्वारा संसूचित किया गया। साथ ही उक्त न्यायादेश के विरुद्ध सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल०पी०ए० सं०-1241/2011 दायर किया गया।

7. एल०पी०ए० सं०-1241/2011 में पारित न्यायादेश के आलोक में आदेश सं०-16773 दिनांक 24.10.2013 द्वारा श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को स्थगित किए जाने से संबंधित विभागीय पत्रांक 1828 दिनांक 14.05.2010 को निरस्त किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस मामले में विभाग का पक्ष रखने के लिए श्री रामेश्वर प्रसाद दास, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

8. उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर विभागीय जॉच आयुक्त के पत्रांक 125/गो० दिनांक 06.08.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री झा के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

9. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 12310 दिनांक 13.09.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन की प्रति श्री झा को उपलब्ध कराते हुए उनसे जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री झा द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 17.09.2018 एवं दिनांक 22.11.2018 समर्पित किया गया।

10. श्री झा के विरुद्ध गठित आरोप, अपर विभागीय जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन पर श्री झा के अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि श्री झा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं घोर कदाचार का उक्त कृत्य का आरोप प्रमाणित है। साथ ही यह भी पाया गया कि श्री झा को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा आरोपों को खण्डित करने हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उन्हें निर्दोष साबित करता हो।

11. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार झा के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(X) के संगत प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री अनिल कुमार झा, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति अवर सचिव (प्रवर कोटि सहायक वरीयता

क्रमांक-622/91), उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(X) के संगत प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अनिल कुमार झा, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति अवर सचिव (प्रवर कोटि सहायक वरीयता क्रमांक-622/91), उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 664-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>